



न्यायालय :- श्रीमान् राजस्व मन्त्रक रवाफिदर [ मणपुरा ]

प्रकरण नैमां / 2001-2000 निगरानी - 2234-II/2001

श्री कृ 401 2111  
26/11/2001  
220

नारायणलाल पुत्र गंगाराम वैश्य निवासी गंगाराम कापुरा  
बानमोर तहसील व जिला सुरैना मणपुरा

बनाह ----- आवेदक

मणपुरा शासन ----- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आवेदक दिनांक 29-8-2001। न्यायालय श्रीमान् अतिरुक्त  
महोदय जल संभाग सुरैना मणपुरा 84/2000-2001। समेक निगरानी-  
अन्तर्गत धारा 59 भूरा राजस्व संहिता

श्रीमान्,

प्रकरण के तब्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1/ यद्यपि, आवेदक द्वारा ग्राम गंगाराम कापुरा मौजा पंचाल  
तहसील बानमोर में स्थित अपने भूमिस्वामित्व हकदार का आधिकार्य  
की भूमि सर्वे नं० 176 रकबा 10 विस्वा से इसी गाँवकी प्राकृती  
भूमि सर्वे नं० 483 रकबा 8 विस्वा को विनियम स्वीकार किये जाने  
बाबत आवेदन अधिनस्थ न्यायालय जजेक्टर महोदय सुरैना के समक्ष प्रस्तुत  
किया। जो मणपुरा 84/9-98 8-19-4 पर कार्य होकर आदेश दिनांक  
29-12-99 को लागू एवं साक्ष्य के बिना किसी आपत्ति पर  
विनियम स्वीकार करते हुए प्रासकीय अन्तर की राशि 1000=00  
रकबा जमा किये जाने का आदेश दिया। इस मामले की जाँच तहसीलदा  
बानमोर से कराई गई व इत्फाद जारी किये गये निर्धारित शर्तों में  
कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई नगर पालिका परिषद बानमोर ने अपने  
पत्र दिनांक 4-11-89 से विनियम स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति  
व्यक्त की। पटवारी मौजा का कथन लोकाह किया गया विनियम ही  
जाने वाली भूमि एक ही गाँवकी होने से समान मूल्य की बताया गया  
सर्वे नं० 483 पटवारी अभियोग में नरेशा अंगिक है किन्तु मणपुरा पर नरेशा  
सर्वे नं० 176 भूमि-समता होने से कृषि योग्य है आवेदक की भूमिस्वामि

26/11/2001

नारायणलाल

50

42

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2234-दो/2001

जिला-मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 24.2.2004 से लगातार अनुपस्थित हैं। प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 4-4-2014 तक नियत होता रहा किन्तु 24.2.2004 से 4-4-14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे। वहीं सुनवाई दिनांक 4-4-2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2001 से लंबित चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	